

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(36) ग्रावि-5/पीएमएवाई-जी./District. Information / 2018-19 जयपुर, दिनांक 15 फरवरी 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय समसख्यक पत्र दिनांक 13.02.2019

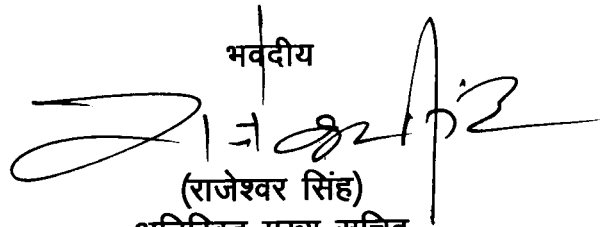
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अन्तर्गत पात्रता के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले परिवारों की पहचान व जोड़े जाने के क्रम में गतिविधिवार समयावधि निर्धारित कर वचित पात्र परिवारों का चिन्हीकरण कर वरीयता सूची में शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया है, इस क्रम में दिनांक 23 व 24 फरवरी 2019 को विशेष ग्रामसभायें आयोजित की जानी है।

योजनान्तर्गत वरीयता सूची के वरीयता क्रमानुसार आवास स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। वरीयता सूची में शामिल अपात्र लाभार्थियों को हटाये जाने हेतु आवास साफ्ट पर "रिमांड मॉड्यूल" उपलब्ध है, इन अपात्र लाभार्थियों को हटाये जाने के उपरान्त ही वरीयता सूची के निचले क्रम के लाभार्थी को आवास स्वीकृत किया जा सकता है। अतः उक्त संबंध में वरीयता सूची में शामिल अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने हेतु आयोजित की जा रही विशेष ग्रामसभाओं में अपात्र लाभार्थियों की सूची संबंधित ग्रामसभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावें।

योजनान्तर्गत SECC - 2011 के आधार पर वरीयता सूची तैयार की गई है। उक्त सूची में शामिल लाभार्थियों के ग्राम/ग्राम पंचायत के परिवर्तन होने के कारण स्वीकृति जारी नहीं हो पा रही है, इस क्रम में जिस ग्राम/ग्राम पंचायत में कोई स्वीकृति जारी नहीं होने पर ही रीमैपिंग जा सकती है इस हेतु संबंधित दोनों ग्राम पंचायतों की नवीन वरीयता सूची एवं ग्राम सभा रिजोल्यूशन की आवश्यकता होगी अतः SECC Remapping के प्रकरण भी उक्त विशेष ग्राम सभाओं में अनुमोदित कराये जावें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत 5 प्रतिशत आवास विशेष योग्यजन को आवंटित किये जाने का प्रावधान है, परन्तु योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा में ज्ञात हुआ है कि राज्य में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक क्रमशः 442, 404 एवं 242 आवास ही विशेष योग्यजन को स्वीकृति किये गये हैं अतः इन ग्रामसभाओं में पात्रता सूची में शामिल सभी विशेष योग्यजन को चिन्हित कर प्राथमिकता से आवास स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायती राज विभाग।
2. संयुक्त सचिव (ग्रा.आ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।


स्टेट नोडल अधिकारी PMAY-G